करनाल में तिरंगे के नाम पर लूट : डिपो संचालक नहीं दे रहे बिना झंडा लिए राशन, विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप

करनाल। डिपो संचालक नहीं दे रहे बिना झंडा लिए राशन, विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप करनाल, हरियाणा के जिले करनाल में गरीब लोगों को इस माह का राशन लेना मंहगा पड़ रहा है। राशन कार्ड धारक अगर इस महीने का राशन लेने के लिए डिपो होल्डर के पास जा रहे हैं तो पहले उन्हें 20 रुपए का तिरंगा झंडा दिया जा रहा है। उसके बाद ही उन्हें राशन मिल रहा है। ऐसे कई मामले सोमवार शाम को सीएम सिटी करनाल के हेमदा गांव सहित कई जगहों पर देखने को मिले। कई जगह पर इसका विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी कई डिपो संचालकों द्वारा बिना तिरंगा के गरीब लोगों को राशन नहीं दिया गया।

वहीं इस मामले को लेकर जब डिपो संचालकों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि विभाग के अधिकारियों द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी राशन कार्ड धारक को बिना तिरंगा लिए राशन नहीं दिया जाए। विभाग के द्वारा पहले ही एडवांस में उनसे 20 रुपए तिरंगे झंडे के हिसाब से ले लिए गए हैं। हर डिपो पर 168 के करीब तिरंगे झंडे दिए गए हैं।

राशन कार्ड धारकों ने विरोध करते हुए कहा कि वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब घर का राशन खत्म हो गया था तो सोमवार से राशन मिलना शुरू हुआ। किसी से पैसे उधार में उठाकर राशन लेने आए हैं। उसके बाद डिपो होल्डर कहता है कि पहले 20 रुपए तिरंगे झंडे के देने होंगे, तभी राशन मिलेगा।

लोगों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार गरीबों की हितैषी बनने का ढोंग कर रही है। वहीं सरकार व अधिकारी इस तरह से गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर सरकार को हर घर तिरंगा लगवाना है तो गरीब लोगों को तिरंगा फ्री में देना चाहिए था।

कुछ लोगों का कहना है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी बीजेपी अपने झंडे फ्री वितरित करती है जो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा क्यों नहीं फ्री में बांटा जाता। राशन नहीं मिलने का एक मैसेज रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ। इसमें डिपो धारक ने लिखा है कि डिपो से जुड़े सभी राशन कार्ड धारक 20 रुपए लेकर झंडा लेने पहुंचे। झंडा न लेने वालों को अगस्त महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, जिले में करीब 400 से ज्यादा राशन डिपो हैं। सरकार द्वारा इन सभी को झंडा वितरण केंद्र बनाया गया है। सूत्रों की मानें तो खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से हर डिपो को 168 झंडे बांटने के लिए दिए गए हैं। उन्होंने 3200 देकर खरीदे हैं।

सरकार व प्रशासन के इस फैसले का लोगों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने कहा कि सरकार व प्रशासन के अधिकारी इस तरह से देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। गरीब लोगों पर झंडा लेने के लिए गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है।

लोगों ने कहा कि अगर यह तिरंगा हम बाजार से लेने जाएं तो यह हमें 5 रुपए में मिल जाता है और डिपो होल्डर व प्रशासनिक अधिकारी तिरंगे झंडे के नाम पर लोगों से मोटे पैसे वसूल रहे हैं। इस मामले को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

शाही फरमान: झंडा नहीं तो राशन नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) जनता की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिये नरेन्द्र मोदी एक कुशल मदारी की तरह देशवासियों को बंदर की तरह नचाने में काफ़ी महारत रखते हैं। कभी थाली बजवाते हैं तो कभी रात के नौ बजे लाइटें बंद करवा कर दीये जलवाते हैं तो कभी हिन्दू-मुस्लिम का खेल खेलवाते हैं।

इसी श्रृंखला में मोदी जी ने **'हर घर तिरंगा'** व तिरंगा यात्राओं का पाखंड देश भर में बिखेर दिया है। जो इनके पाखंड में शामिल न हों उसे देशद्रोही बताया जाता है। अब से पहले जब इस तरह की तिरंगा यात्रायें व घर-घर झंडे का अभियान नहीं चलता था तो क्या तमाम भारतवासी देशद्रोही थे? क्या विडम्बना है जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की बजाय अंग्रेज हकूमत के तलवे चाटे और सदैव तिरंगे को अशुभ बताते रहे, वहीं आज देशभक्ति का प्रमाणपत्र देने वाले बन बैठे।

नागपुर से अपनी जायज मांगों को लेकर 168 युवक हाथों में तिरंगा लेकर दिल्ली की ओर पैदल रवाना हुए थे, उनकी तिरंगा यात्रा मोदीजी को पसंद नहीं आई। इसलिये पूरे रास्ते उनके ऊपर हर तरह का पुलिसिया जुल्म ढाया गया। एक ओर जहां कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के साथ-साथ, पुलिस अफ़सरों से उनके पैर दबवाये गये वहां इन तिरंगा यात्रियों पर पुलिस ने डंडे बरसाये।

देश भर की जनता उनके इशारे पर किस तरह नाचती है, दर्शाने के लिये मोदीजी ने तमाम सरकारी मशीनरी को काम पर लगा दिया है। अपने तमाम प्रशासनिक काम छोड़कर अधिकारीगण जनता पर झंडे थोपने पर जुटे हैं। कहीं स्कूली विद्यार्थियों पर तो कहीं राशन डिपुओं पर झंडे थोपे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक संदेश में राशन डिपू वाले कह रहे हैं कि झंडा नही खरीदेंगे तो राशन नहीं मिलेगा। यद्यपि प्रशासनिक अधिकारी अपने ऐसे किसी भी फरमान से तुरन्त मुकर जाते हैं क्योंकि ये जबानी होते हैं।

ज़िले भर में शायद ही कोई राशन डिपो वाला ऐसा होगा जो राशन बेचने में डंडी न मारता हो। कोई विरला ही डिपो धारक ऐसा होगा जिसे फूड सप्लाई वाले जब चाहें पकड़कर अंदर न कर दें। लिहाजा अपनी इसी धौंस-पट्टी के बल पर इस विभाग ने प्रत्येक डिपू वाले को 168 झंडे देकर बतौर कीमत उनसे 3200 रुपये अग्रिम वसूल कर लिये हैं। झंडे बिके न बिके उनकी बला से। विदित है कि इन डिपुओं से समाज का निम्न वर्ग ही राशन, खरीदता है। अब देखना है कि कितने गरीब लोग डिपो धारकों के शिकंजे में फसते हैं?

जबरदस्ती झंडा बेचने वाले राशन डिपो होल्डर का लाईसेंस रद्द : उपायुक्त अनीश यादव

करनाल। तिरंगे झंडे की बिक्री को लेकर राशन कार्ड धारकों को गुमराह करने वाले एक डिपो होल्डर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसका लाईसेंस निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त अनीश यादव ने इस संबंध में बताया कि निसिंग खंड के गांव दादुपुर के साथ अटैच चिड़ाव-हेमदा का एक डिपो होल्डर राशन कार्ड धारकों को यह कहकर झंडे की बिक्री कर रहा था कि 20 रुपये में झंडा लेंगे तो राशन मिलेगा, अन्यथा नहीं। जैसे ही यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया तो लोगों को गुमराह करने वाले डिपो होल्डर के खिलाफ तुरंत कार्यवाही अमल में लाते हुए उसका लाईसेंस निलंबित कर दिया है।

उपायुक्त ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बातों से गुमराह करता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। उचित मूल्य की दुकानें और अन्य बिक्री केन्द्रों से कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से महज 20 रुपये की कीमत पर झंडा खरीद सकता है। जनता की सहूलियत के लिए डिपो होल्डरों को, प्रशासन की ओर से 88400 झंडे उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने आम जनता से यह भी अपील की है कि इस तरह की बातों से कोई भी व्यक्ति गुमराह न हो और जिसकी इच्छा हो वह झंडा खरीद सकता है।

शर्मनाक

खट्टर सरकार अपने झूठ को छिपाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों तक को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रही है। सारी जनता जानती है कि उपायुक्त के आदेश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अपने तमाम राशन डिपुओं पर बिक्री के लिए झंडे रखे हुये हैं। इन झंडों की कीमत उनसे अग्रिम वसूल कर ली गयी है। अब राशन डिपो वाले इन झंडों को बेचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इस मामले में जिस डिपो होल्डर का लाईसेंस रद्द किया गया है उसका दोष केवल इतना है कि उसने कैमरे पर सरकार की पोल चौड़े में खोल दी। इससे परेशान होकर सरकार ने उसका लाईसेंस रद्द कर दिया। इसी भय एवं धौंस के चलते तमाम डिपो होल्डर कार्डधारकों को जबरन झंडे बेच रहे हैं।

शिक्षा की बदहाली से चिंतित बच्चे व अभिभावक डीसी से मिले

करनाल। हरियाणा के सीएम सिटी करनाल के गांव चोरकारसा की छात्राएं और ग्रामीण मंगलवार को सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी और अन्य समस्याओं को लेकर डीसी कार्यालय पहुंची। बेटे-बेटियां व उनके अभिभावक स्कूल मे शिक्षकों की कमी को दूर करने और स्कूल को अपग्रेड करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि बच्चे पढ़ना चाहते है, लेकिन स्कूल में असुविधाओं के चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों को चिंता सता रही है कि उनके बच्चों का बिना पढ़ाई के क्या भविष्य होगा खासकर बेटियों का।

150 बच्चों के लिए 3 टीचर

मंगलवार दोपहर बाद गांव चोरकारसा के बच्चे व उनके अभिभावकों ने जिला सचिवालय में पहुंचकर डीसी से मुलाकात की। बेटियों ने डीसी से गुहार लगाई कि गांव के स्कूल को अपग्रेड किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में 150 के करीब बच्चे है, लेकिन शिक्षक तीन ही है। ऐसे में शिक्षकों की भारी कमी के कारण उन्हें परेशानियों झेलनी पड़ रही है। अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो तो उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। यह बात छात्रा सपना, रूमा, महक ने कही।

स्कूल में टीचरों की कमी

बेटियों ने कहा कि वह पढ़ाना चाहती है, लेकिन उनके अभिभावक उन्हें गांव से बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते। बाहर भेजने में काफी दिक्कतें है, आने जाने के लिए कोई साधन तक नहीं। इन हालात में कैसे बेटियां स्कूलों में जाकर पढ़ पाएगी। स्कूल को अपग्रेड किया जाए, साथ ही स्कूल में स्टाफ की भारी कमी हैं। जब स्कूलों में टीचर ही नहीं है, तो बच्चों का क्या भविष्य है। हमारी मांग है कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता खासकर बेटियों को गांव से बाहर नहीं भेजना चाहते। क्योंकि बाहर जाने में काफी दिक्कतें है।

10वीं के बाद पढ़ने के लिए जाना पड़ता है बाहर

डीसी से मिलने पहुंची दसवीं की छात्रा सपना ने कहा कि गांव में सरकारी स्कूल केवल 10वीं कक्षा तक है, हम दसवीं के बाद भी पढ़ाना चाहती है। लेकिन चाह कर भी नहीं पढ़ पाती। क्योंकि गांव से बाहर जाने के लिए सार्वजनिक बस सुविधा उपलब्ध नहीं है और नहीं ही गरीब अभिभावकों के पास आर्थिक संसाधन। इन सब दिक्कतों की वजह से बेटियों को सिर्फ दसवीं तक ही पढ़ा पाते है। उन्होंने कहा कि बेटे तो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव या शहरों में जा सकते है। लेकिन ल?कियां नहीं उनकी मांग है कि गांव के स्कूल को 12वीं तक किया जाए साथ ही स्कूल में अध्यापकों की संख्या पूरी की जाए ताकि पढ़ाई बाधित न हो सकें।

12वीं तक अपग्रेड हो स्कूल

छात्रा महक ने कहा कि गांव में 12वीं तक स्कूल बनाया जाए, साथ ही स्कूल में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। माता पिता उन्हें दसवीं के बाद नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि गांव में 12 वीं तक की पढ़ाई की सुविधा नहीं है, बाहर वे भेजना नहीं चाहते। उनकी मांग है कि गांव के सरकारी स्कूल को अपग्रेड किया जाए साथ ही स्कूल में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए।